



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 मई 2017—ज्येष्ठ 6, शक 1939

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 मई 2017

क्र. एफ 87-198-15-11-75.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह-दिसम्बर, 2014 में संपन्न नगर परिषद्, कुरावर, जिला राजगढ़ (म. प्र.) के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में सुश्री मालती भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 04 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक सुश्री मालती को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ (म. प्र.) के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ (म. प्र.) के पत्र क्रमांक 459, दिनांक 07 फरवरी 15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, सुश्री मालती द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ से प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री मालती को आयोग की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 30 मार्च 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली की जानकारी जिले से आयोग को प्राप्त होने के उपरांत आयोग के पत्र दिनांक 14 मई 2015 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-राजगढ़ से इस आशय की रिपोर्ट चाही गई कि यदि नोटिस की तामीली के उपरांत अभ्यर्थी, सुश्री मालती द्वारा निर्वाचन व्यय लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी स्वीकार्यता/विश्वसनीयता के संबंध में स्पष्ट अभिमत से आयोग को अवगत कराया जाये।

इस सम्बन्ध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला-राजगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 621, दिनांक 03 अप्रैल 2017 में प्रतिवेदित किया गया कि-मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कुरावर के प्रतिवेदन दिनांक 30 मार्च 2017 के अनुसार सुश्री मालती द्वारा उनको भी इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सूचित करने के बाद भी निर्वाचन व्यय लेखा के संबंध में कोई अभ्यावेदन सुश्री मालती द्वारा प्रस्तुत ना करने के कारण नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

जिले से उक्ताशय की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री मालती सिंह के विलम्ब से प्रस्तुत किये गए निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-राजगढ़ के माध्यम से नोटिस दिनांक 18 अप्रैल 2017 जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 16 मई 2017 को बुलाया गया।

अभ्यर्थी सुश्री मालती को जारी उपर्युक्त सूचना-पत्र व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व तामील होने की सूचना उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.), जिला-राजगढ़ के ज्ञापन 04-5-2017 के संलग्न आयोग को प्राप्त हो गई थी।

अभ्यर्थी सुश्री मालती को नोटिस तामीली की सूचना प्राप्त हो जाने के उपरांत वे आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तथे तिथि दिनांक 16 मई 2017 को उपस्थित हुईं। सुनवाई की दौरान वे व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में कोई औचित्यपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकीं।

अतः, उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, सुश्री मालती द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस विलम्ब के संबंध में कोई औचित्यपूर्ण साक्ष्य ही प्रस्तुत किए जा सके, जिसके आधार पर उनको राहत दी जा सके।

अतः, इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ग के उपबन्धों के अधीन अभ्यर्थी, सुश्री मालती को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् कुरावर, जिला-राजगढ़ (म. प्र.) का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 मई 2017

क्र. एफ 87-310-15-11-78.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह-अगस्त, 2015 में संपन्न नगर परिषद्, कोटर, जिला-सतना (म. प्र.) के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में सुश्री विनोद कु. बंशपती सिंह बल्लू भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 अगस्त 2015 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 15 सितम्बर 2015 तक, सुश्री विनोद कु. बंशपती सिंह बल्लू को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म. प्र.) के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म. प्र.) के पत्र क्रमांक 546, दिनांक 01 अक्टूबर 15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, सुश्री विनोद कु. बंशपती सिंह बल्लू द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखे प्रस्तुत ही नहीं किये गये।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना से आयोग प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सुश्री विनोद कु. बंशपती सिंह बल्लू को आयोग की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2015 जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली की जानकारी जिले के पत्र दिनांक 18 नवम्बर 2016 के संलग्न आयोग को प्राप्त हो जाने के उपरान्त आयोग के पत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2016 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-सतना से इस आशय की रिपोर्ट चाही गई कि यदि नोटिस की तामीली के उपरान्त अभ्यर्थी, सुश्री विनोद कु. बंशपती सिंह बल्लू द्वारा विलम्ब से निर्वाचन व्यय लेखे या अभ्यावेदन जिला स्तर पर दाखिल किए गए हों तो उनकी विश्वसनीयता/स्वीकार्यता बावत् अभिमत से आयोग को अवगत कराया जाये।

इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला सतना के आयोग को प्रेषित के ज्ञापन क्रमांक 1391, दिनांक 07 अप्रैल 2017 में प्रतिवेदित किया गया कि—तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर नगर परिषद्, कोटर जिला-सतना से उक्त संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नोटिस तामीली इस कार्यालय में उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही जिला स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा एवं कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

जिले से उक्ताशय की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने जाने के उपरान्त आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी, सुश्री विनोद कु. बंशपती सिंह बल्लू के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-सतना के माध्यम से नोटिस दिनांक 25 अप्रैल 2017 जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 16 मई 2017 को बुलाया गया।

अभ्यर्थी सुश्री विनोद कु. बंशपती सिंह बल्लू को जारी उपर्युक्त सूचना-पत्र तामील होने की जानकारी जिले के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 6 मई 2017 के संलग्न प्राप्त हो गई थी।

अभ्यर्थी सुश्री विनोद कु. बंशपती सिंह बल्लू को नोटिस तामीली की सूचना प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी वे न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन ही आयोग को प्राप्त हुआ।

अतः, उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, सुश्री विनोद कु. बंशपती सिंह बल्लू द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस निमित्त कोई अभ्यावेदन ही प्रस्तुत किया गया।

अतः, इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32 ग के उपबन्धों के अधीन अभ्यर्थी, सुश्री विनोद कु. बंशपती सिंह बल्लू को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् कोटर, जिला-सतना (म. प्र.) का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

## आदेश

भोपाल, दिनांक 27 मई 2017

क्र. एफ 87-310-15-11-79.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह-अगस्त, 2015 में संपन्न नगर परिषद्, कोटर, जिला-सतना (म. प्र.) के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में **सुश्री सत्यवती पाण्डेय** भी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 अगस्त 2015 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 15 सितम्बर 2015 तक, **सुश्री सत्यवती पाण्डेय** को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म. प्र.) के समक्ष दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना (म. प्र.) के पत्र क्रमांक 546, दिनांक 01 अक्टूबर 15 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के अनुसार अभ्यर्थी, **सुश्री सत्यवती पाण्डेय** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखे प्रस्तुत ही नहीं किये गये।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना से आयोग प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **सुश्री सत्यवती पाण्डेय** को आयोग की ओर से कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2015 जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली की जानकारी जिले के पत्र दिनांक 18 नवम्बर 2016 के संलग्न आयोग को प्राप्त हो जाने के उपरान्त आयोग के पत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2016 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-सतना से इस आशय की रिपोर्ट चाही गई कि यदि नोटिस की तामिली के उपरान्त अभ्यर्थी, **सुश्री सत्यवती पाण्डेय** द्वारा विलम्ब से निर्वाचन व्यय लेखे या अभ्यावेदन जिला स्तर पर दाखिल किए गए हों तो उनकी विश्वसनीयता/स्वीकार्यता बावत् अभिमत से आयोग को अवगत कराया जाये।

इस सम्बन्ध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सतना के आयोग को प्रेषित के ज्ञापन क्रमांक 1391, दिनांक 07 अप्रैल 2017 में प्रतिवेदित किया गया कि—तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर नगर परिषद्, कोटर जिला-सतना से उक्त संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नोटिस तामिली इस कार्यालय में उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही जिला स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में भी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा एवं कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

जिले से उक्ताशय की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त होने जाने के उपरान्त पर आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी, **सुश्री सत्यवती पाण्डेय** के निर्वाचन व्यय लेखों पर अंतिम निर्णय लिए जाने हेतु उन्हें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-सतना के माध्यम से नोटिस दिनांक 25 अप्रैल 2017 जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 16 मई 2017 को बुलाया गया।

अभ्यर्थी **सुश्री सत्यवती पाण्डेय** उपर्युक्त सूचना-पत्र तामिल होने की जानकारी जिले के आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 6 मई 2017 के संलग्न प्राप्त हो गई थी।

अभ्यर्थी **सुश्री सत्यवती पाण्डेय** को नोटिस तामिली की सूचना प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी वे न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत उपर्युक्त तिथि को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुई और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन ही आयोग को प्राप्त हुआ।

अतः, उपर्युक्त निववेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अभ्यर्थी, **सुश्री सत्यवती पाण्डेय** द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही इस निमित्त कोई अभ्यावेदन ही प्रस्तुत किया गया।

अतः, इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ग के उपबन्धों के अधीन अभ्यर्थी, सुश्री सत्यवती पाण्डेय को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् कोटर, जिला-सतना (म. प्र.) का पार्षद् या अध्यक्ष होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( सुनीता त्रिपाठी )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.